RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 275 | दि. 05-02-2019 मंगलवार | वि.सं. 2075 | महासुद -०१ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

घटना स्थल से ही काम करेंगी सीएम ममता बेनर्जी

ममता Vs सीबीआई : राज्यपाल ने गृह मंत्रालय को भेजी गोपनीय रिपोर्ट

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता सरकार के ताजा विवाद को लेकर राज्य के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को भेजी है। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्रालय सीबीआई के काम में बाधा डालने के आरोप में वहां मौजूद आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है। वहीं खबरें आ रही हैं ममता बनर्जी का धरना अभी और लंबा चल सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी धरना चलने तक धरनास्थल से काम करेंगी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गवर्नर से सीबीआई के अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की करने और हिरासत में लिए जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले पर गृह मंत्रालय को अवगत कराने को कहा था। इसके बाद गवर्नर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर इस मामले में तुरंत ऐक्शन लेकर विवाद को खत्म कराने को कहा था। इस मामले पर बीजेपी और विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे के सामने आ गई हैं। इसे लेकर

ममता बनर्जी का धरना अभी और लंबा चल सकता है : ताजा विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी-विपक्षी पार्टियां एक-दूसरे के सामने आ गई हैं

लोकसभा और राज्य सभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह देश में पहली बार है कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई और उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़प लेनेवाली कंपनी के खिलाफ सीबीआई को जांच की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी और मामले की पूछताछ के लिए ही सीबीआई की टीम रविवार को राजीव कुमार के घर पहुंची थी। सीबीआई को राजीव के घर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब देते हुए राजनाथ ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और लगातार समन के बावजूद पूछताछ में हिस्सा लेने नहीं आए थे। राजनाथ ने कहा कि पूछताछ के लिए पहुंची टीम को पुलिस ने रोका और बलपूर्वक हिरासत में ले लिया था। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि ऐसी घटना से देश के संघीय ढांचे को खतरा है। राजनाथ सिंह ने आगे बताया कि उन्होंने मामले पर बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी से भी बात की है। और उनसे मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी का धरना अभी और लंबा चल सकता है। ऐसे में ममता बनर्जी धरना चलने तक धरनास्थल से काम करेंगी। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गवर्नर से सीबीआई के अधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की करने और हिरासत में लिए जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले पर गृह मंत्रालय को अवगत कराने को कहा था। इसके बाद गवर्नर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर इस मामले में तुरंत ऐक्शन लेकर विवाद को खत्म कराने को कहा था।सबूत छिपाने के आरोपी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। याचिका में सीबीआई ने कोर्ट से निवेदन किया था कि वह राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दें। साथ ही सीबीआई ने राजीव कुमार पर अबतक हुई इन्वेस्टिगेशन में साथ न देने का आरोप भी लगाया है। सीबीआई द्वारा राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है।

ममता-CBI विवाद पर बोले नीतीश कुमार

चुनाव के ऐलान से पहले कुछ भी हो सकता है

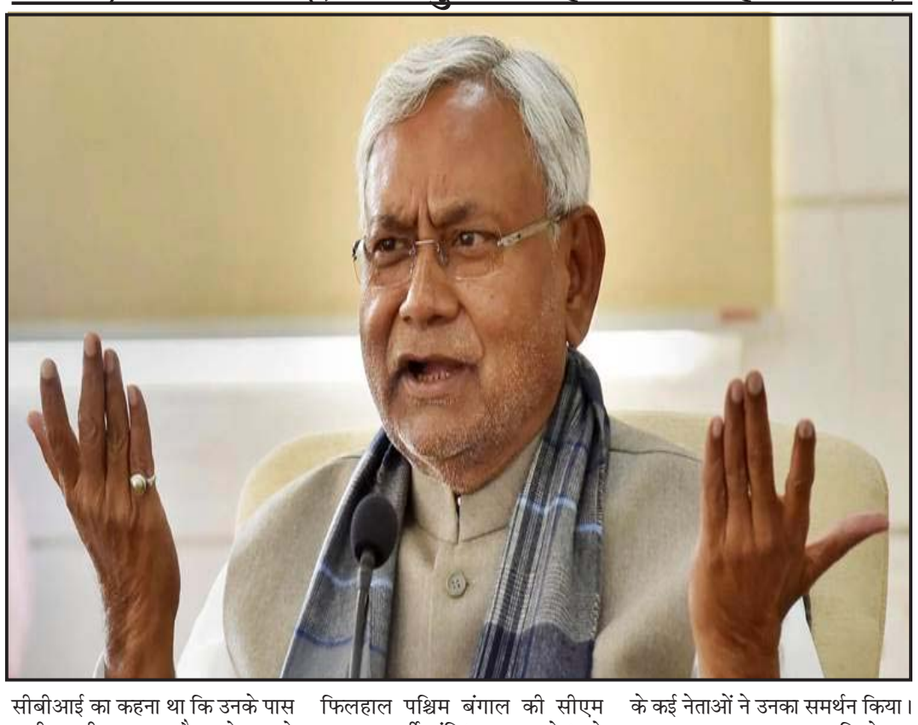

जब तक निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करता, तब तक देश में कुछ भी हो सकता है : नीतीश

(संपूर्ण समाचार सेवा) पटना, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रहे विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश ने कहा कि इस मामले में वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। नीतीश ने सीधे-सीधे कुछ कहने से बचते हुए इशारों में ममता बनर्जी के कदम पर सवाल उठाया। बता दें कि चिट फंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई टीम के पहुंचने के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। नीतीश कुमार ने कहा, इस मामले में वही लोग बता सकते हैं जो इस कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। मैं ऐसी चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। सवालों के जवाब सीबीआई और सरकार देगी। जब तक निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करता, तब तक देश में कुछ भी हो सकता है। सारदा चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई रविवार रात को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची थी। लेकिन वहां कोलकाता पुलिस ने सीबीआई की टीम के ५ लोगों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद ममता बनर्जी मीडिया के सामने आईं और सीबीआई पर बिना जानकारी दिए वहां आने का आरोप लगाया। वहीं

सीबीआई का कहना था कि उनके पास सभी जरूरी कागजात मौजूद थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बंगाल में तख्तापलट करने की कोशिश का आरोप लगाया और धरने पर बैठने का ऐलान किया। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी संविधान बचाओ धरने पर बैठी हैं। यह धरना कोलकाता के मेट्रो चैनल के पास चल रहा है। रविवार को हुए घटनाक्रम के बाद ममता ने जब धरने पर बैठने का ऐलान किया तो विपक्ष के कई नेताओं ने उनका समर्थन किया। राहुल, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश, तेजस्वी यादव, चंद्रबाबू, मायावती, पवार और केजरीवाल आदि ने रविवार रात ही ममता बनर्जी से फोन पर बात की और उनका समर्थन किया।

हाई कोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी

राहत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे पुलिस आयुक्त राजीव कुमार

कलकत्ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार : मामले में मंगलवार को सुनवाई

(संपूर्ण समाचार सेवा) कोलकाता, सारदा और रोजवैली घोटाले में सबूतों को छिपाने के आरोपी कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार सीबीआई पूछताछ के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाई कोर्ट से सीबीआई पूछताछ से अंतरिम राहत मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट राजीव कुमार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। इससे पहले कोलकाता पुलिस के ४ अधिकारी कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे। इन अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ऐसे समय पर उन्हें नोटिस भेज रही है जब सारदा घोटाले में जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई उन्हें प्रताड़ित कर सकती है, इसलिए उन्हें पूछताछ से राहत दी जाए। इन्ही अधिकारियों की तर्ज पर कोलकाता पुलिस के आयुक्त राजीव कुमार ने भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इस तरह पर कोलकाता पुलिस आयुक्त और सीबीआई के बीच जारी जंग हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। उधर, पश्चिम बंगाल में रविवार को सीबीआई अफसरों के कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंचने का मामला सोमवार को लोकसभा में भी छाया रहा। सीबीआई की कार्रवाई का विरोध करते हुए विपक्ष ने इसपर जमकर हंगामा किया, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी। राजनाथ ने कहा कि सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ पहली बार

इस तरह की घटना हुई और उनको हिरासत में लिया गया। सारदा घोटले का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़प लेनेवाली कंपनी के खिलाफ सीबीआई को जांच की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी और मामले की पूछताछ के लिए ही सीबीआई की टीम रविवार को राजीव कुमार के घर पहुंची थी। सीबीआई को राजीव के घर जाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब देते हुए राजनाथ ने कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और लगातार समन के बावजूद पूछताछ में हिस्सा लेने नहीं आए थे।

अयोध्या मामला : जमीन लौटाने की

केंद्र की अर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, आम चुनाव से पहले अयोध्या को लेकर रोज नई हलचल हो रही है। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने गैर-विवादित जमीन वापस लौटाने के लिए अर्जी दी। अब इस अर्जी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता ने लैंड ऐक्विजिशन ऐक्ट की वैधता पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र राज्य की भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकतीकेंद्र सरकार के कदम को भी इस अर्जी में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकती। पिछले सप्ताह ही केंद्र सरकार ने ६७ एकड़ गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के इस कदम का जहां राम जन्मभूमि न्यास ने स्वागत किया था, वहीं कुछ अन्य संगठनों ने इसका विरोध किया। इस

मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रविवार को ही एक कार्यक्रम में सभी दलों से इस पर सहयोग की मांग की थी। केंद्र ने कोर्ट में गैर-विवादित जमीन लौटाने की अर्जी में कहा कि वह गैर-विवादित ६७ एकड़ जमीन इसके मालिक राम जन्मभूमि न्यास को लौटाना चाहती है। इस जमीन का अधिग्रहण १९९३ में कांग्रेस की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। १९९३ में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण ऐक्ट के तहत विवादित स्थल और आसपास की जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और पहले से जमीन विवाद को लेकर दाखिल तमाम याचिकाओं को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सूची के विषयों की आड़ में केंद्र सरकार राज्य की भूमि अधिग्रहित नहीं कर सकती। पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने ६७ एकड़ गैर-विवादित जमीन मूल मालिकों को लौटाने के लिए अर्जी दी थी।सरकार के इस ऐक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस्माइल फारुखी जजमेंट में १९९४ में तमाम दावेदारी वाले सूट (अर्जी) को बहाल कर दिया था और जमीन केंद्र सरकार के पास ही रखने को कहा था और निर्देश दिया था कि जिसके फेवर में अदालत का फैसला आता है, जमीन उसे दी जाएगी।

राजदार को बचा रहीं ममता : बीजेपी का अटैक

धरना कर गठबंधन का नेता बनने की कोशिश : रविशंकर

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना रविवार रात से ही लगातार जारी है। इस बीच ममता सरकार के रवैये के खिलाफ बीजेपी भी आक्रामक हो गई है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी उस राजदार को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो काफी कुछ जानता है। गठबंधन पर तंज कसते हुए प्रसाद ने कहा, धरने के जरिए ममता अपने को नेता के रूप में भी प्रॉजेक्ट कर रही हैं। राहुल गांधी और मायावती को भी पूछना होगा कि उनका क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, बंगाल में क्या हो रहा है? एक पुलिस कमिश्नर नेताओं के साथ धरने पर बैठे हैं ? इसका क्या मतलब है ? धरने पर बैठकर पश्चिम बंगाल की CM दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नक्शेकदम पर चल रही हैं। BJP नेता ने कहा कि हम उम्मीद करेंगे कि भ्रष्टाचार की जांच के खिलाफ एजेंसी

को नहीं झुकना चाहिए। प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी का २०१४ में किया गया एक ट्वीट पढ़कर सुनाया। बीजेपी नेता ने कहा, ८ मई २०१४ में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का बयान ट्वीट किया था कि पश्चिम बंगाल में चिट फंड स्कैम में २० लाख लोगों का पैसा डूब गया है। यह निंदनीय है।' प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार ने २६ मई २०१४ को शपथ ली और नारदा, सारदा और रोज वैली मामलों की जांच इससे पहले शुरू हुई थी। ऐसे में विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, जो बीजेपी, अमित शाह और पीएम मोदी के खिलाफ अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आगे कहा कि ममता ने २६ अप्रैल २०१३ को पोंजी स्कीम्स की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी। उसके अध्यक्ष राजीव कुमार थे, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी समर्थक सुप्रीम कोर्ट गए थे और ९ मई २०१४ को निर्देश दिया गया कि मामले की जांच सीबीआई करेगी। स्ट ने कहा था कि नारदा, सारदा और रोजवैली मामलों के व्यापक ऐंगल की भी जांच की जाएगी। प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सांसद मदन मित्रा, तापस पाल जैसे कई बड़े नेता गिरफ्तार किए गए तब ममता ने कभी भी आलोचना नहीं की। सवाल उठता है कि सारी मर्यादाएं तोड़कर ममता पुलिस कमिश्नर के समर्थन में धरने पर क्यों बैठ गईं। सुदीप बंदोपाध्याय और मदन मित्रा की गिरफ्तारी पर ममता व्याकुल नहीं हुईं तो ८३ बैच के आईपीएस अफसर को बचाने के लिए वह इतनी परेशान क्यों हैं ? ऐसे में संदेह पैदा होता है कि राजदार बहुत जानता है। कमिश्नर को कई बड़ी बातें पता हैं।

संपादकिय

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मनमानी और भाजपा के खिलाफ तानाशाही

क्या इससे बडी विडंबना और कोई हो सकती है कि जो ममता बनर्जी मोदी सरकार की कथित लोकतंत्र विरोधी नीतियों का झंडा बुलंद किए रहती हैं वह खुद भाजपा के खिलाफ तानाशाही भरे रवैये का परिचय देने में संकोच नहीं कर रही हैं? समझना कठिन है कि उनकी सरकार ने किस अधिकार के तहत बालूरघाट में भाजपा की रैली को संबोधित करने के लिए वहां जाने की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी? इस मनमानी रोक के चलते उन्हें फोन से रैली को संबोधित करना पडा। यह किसी राज्य सरकार की ओर से विरोधी दल के नेताओं को अपने यहां सभा–सम्मेलन करने से रोकने का दुर्लभ उदाहरण है। दुर्भाग्य से ममता बनर्जी इस तरह के उदाहरण पेश करने में माहिर होती जा रही हैं। भाजपा की इस रैली में खलल डालने के पहले उनकी सरकार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा में भी इसी तरह की बाधा डाल चुकी है। उनकी सरकार पर यह भी आरोप है कि वह प्रधानमंत्री की रैलियों के दौरान पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रही है। यह तो एक तथ्य ही है कि ममता सरकार कानून एवं व्यवस्था बिगडने का अंदेशा जताकर भाजपा को यात्राएं नहीं निकालने दे रही है। आखिर ऐसी सरकार के मुखिया को लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है? माना कि ममता बनर्जी अपने गुस्से के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों और मर्यादाओं को ताक पर रख दें। मुश्किल यह है कि वह ऐसा डंके की चोट पर कर रही हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह भान ही नहीं है कि वह एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति ऐसा रवैया शोभा नहीं देता। इस तरह का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विपरीत है। इससे केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक छवि को भी चोट पहुंचती है। ममता बनर्जी अपने मनमाने तौर–तरीकों से अपना ही नुकसान कर रही हैं। आखिर राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता दिखा रहा कोई नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकता है? अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति ममता का असहिष्णु रवैया कुल मिलाकर उन वामदलों की ही याद दिला रहा है जिनके कठोर शासन से उकता कर लोगों ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी थी। वह तो वाम दलों को भी मात दे रही हैं। वह भाजपा और मोदी सरकार के प्रति इस हद तक असहिष्णुता से भरी हुई हैं कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ठुकराने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के प्रति भी दुर्भावना का प्रदर्शन करने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी अपने मनमाने आचरण से यही दर्शा रही हैं कि सत्ता में आने के बाद कुछ नेता किस तरह बेलगाम हो जाते हैं। इस पर यकीन करना कठिन है कि यह वही ममता बनर्जी हैं जो संघीय ढांचे की रक्षा के लिए चिंता जताया करती थीं। उनकी सरकार का रवैया तो संघीय ढांचे की मूल भावना पर ही प्रहार करने वाला है। क्या ममता बनर्जी को साथ लेकर महागठबंधन बनाने वाले नेता यह देखेंगे कि उनकी एक सहयोगी कैसा अलोकतांत्रिक आचरण कर रही हैं?

हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की नाकामियों की अनदेखी करना राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाना है

(जी.एन.एस.) बेंगलुरु के पास लडाकू विमान मिराज–2000 का दुर्घटनाग्रस्त होना और उसमें वायु सेना के दो अनुभवी पायलटों की मौत हो जाना एक बेहद गंभीर घटना है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि इस घटना पर गंभीरता का परिचय दिया जाए, बल्कि यह भी है कि उन कारणों की तह तक सचमुच जाया जाए जिनके चलते देश ने एक लडाकू विमान के साथ अपने दो पायलट भी खो दिए। एक साथ दो पायलटों की मौत इसलिए बडा नुकसान है, क्योंकि लडाकू विमानों के पायलट बेहद गहन प्रशिक्षण के बाद तैयार होते हैं। चूंकि उनके प्रशिक्षण में समय के साथ तमाम संसाधन भी लगते हैं इसलिए परीक्षण उडान के दौरान उनकी मौत राष्ट्रीय क्षति है। लडाकू विमानों के साथ कछ न कुछ जोखिम रहता है, लेकिन आम तौर पर परीक्षण उडानों के दौरान कोई गडबडी होने पर पायलट खुद को बचा लेते हैं। बेंगलुरु में ऐसा नहीं हो सका। यहां मिराज–2000 लडाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यदि उसे उन्नत करने वाली हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई है तो यह स्वाभाविक है। अगर यह माना जा रहा है कि एचएएल की खामी परीक्षण उडान पर निकले पायलटों पर गाज बनकर गिरी तो इसके लिए यह सरकारी कंपनी अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। लडाकू विमानों की मरम्मत करने और उन्हें उन्नत बनाने में एचएएल का रिकार्ड बहुत ही खराब है। चूंकि उनके प्रशिक्षण में समय के साथ तमाम संसाधन भी लगते हैं इसलिए परीक्षण उडान के दौरान उनकी मौत राष्ट्रीय क्षति है। लडाकू विमानों के साथ कछ न कुछ जोखिम रहता है, लेकिन आम तौर पर परीक्षण उडानों के दौरान कोई गडबडी होने पर पायलट खुद को बचा लेते हैं। बेंगलुरु में ऐसा नहीं हो सका। यहां मिराज–2000 लडाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद यदि उसे उन्नत करने वाली हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल रक्षा विशेषज्ञों और पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ आम लोगों के निशाने पर आ गई है तो यह स्वाभाविक है। एचएएल की ओर से तैयार अथवा उन्नत किए गए विमान जिस तरह हादसे का शिकार होते रहते हैं उसे देखते हुए किसी को इस सवाल का जवाब देना ही होगा कि आखिर इस सरकारी कंपनी के दोयम दर्जे के कामकाज की अनदेखी कब तक की जाती रहेगी? यह अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने वाली सरकारी कंपनियों के बेजा बचाव की प्रवृत्ति का ही परिणाम है कि रक्षा सामग्री के उत्पादन के मामले में भारत का प्रदर्शन बहुत ही गया–बीता है। अब जब रक्षा विशेषज्ञों के साथ वायु सेना प्रमुख भी एचएएल के कामकाज से संतुष्ट नहीं तब फिर यह जरूरी है कि नीति–नियंता चेत जाएं।

मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ

सेना के साथ मुठभेड़ के दौरान ३ आतंकी ढेर

हिज्बुल मुजाहिद्दीन के गढ़ कहे जाने वाले पुलवामा के त्रासल इलाके में सेना ने आतंकियों को मार गिराया

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर, हिज्बुल मुजाहिद्दीन के गढ़ कहे जाने वाले पुलवामा के त्रासल इलाके में सेना ने गुरुवार को तीन आतंकियों को मार गिराया है। खुफिया सूत्रों से इलाके में आतंकियों की मूवमेंट होने की जानकारी मिलने के बाद हुई इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद से ही पुलवामा जिले में भारी हिंसा हुई है। सेना के मुताबिक, गुरुवार सुबह खुफिया सूत्रों से जवानों को पुलवामा में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट मिले थे। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सेना की ४२ राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू–कश्मीर पुलिस की एसओजी और सीआरपीएफ ने त्रास के पहाड़ी इलाकों में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरु किया। इस कार्रवाई के दौरान ही जंगल में छिपे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई कर आतंकियों की घेराबंदी की। इस अभियान में सेना ने ३ आतंकियों को मार गिराया, वहीं ऑपरेशन में सेना का एक जवान घायल हुआ। बाद में हालत गंभीर होने पर उन्हें उधमपुर स्थि कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना ने एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला–बारूद बरामद किया है। त्राल में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलवामा जिले में काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। इस दौरान अवंतिपोरा और त्राल के कुछ इलाकों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए। सीआरपीएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को खदेड़ा।

साहित्य में साहस का प्रदर्शन- अंग्रेजी लेखक के अपेक्षा हिंदी के व्यंग्य लेखक अधिक साहसी होते हैं

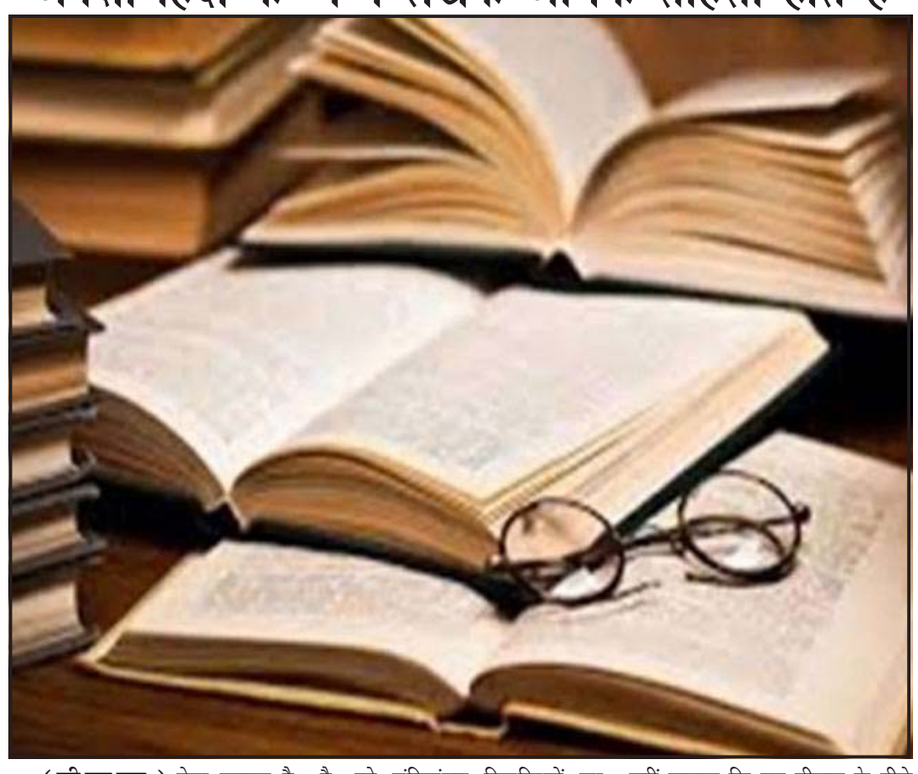

(जी.एन.एस.) मेरा मानना है कि भयभीत लोगों का साहस और बेमौका बोल प?ने का शौक साहित्य, विशेषकर व्यंग्य को जन्म देता है। आत्मा के भीतर की कुलबुलाहट जब मध्यमवर्गीय भीरूता के संपर्क में आती है तो व्यक्ति व्यंग्य लिखने लगता है। इसका आनंद यह होता है कि लेखक मन ही मन अपने पराक्रम पर मुग्ध हो लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि तीर चला किधर और लगा कहां? हिंदी के व्यंग्य लेखक प्राय- अधिक साहसी होते हैं। इधर कुछ समय से अंग्रेजी लेखक भी साहसी होने का दावा पेश करते रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूतों पर दावा ठोकते हुए वे प्रतिष्ठित और साधन–संपन्न साहित्य सम्मेलनों के मंच से सरकार को कोसते हैं और मजरूह की मासूमियत ओडकर तंत्र के दमन की शिकायत करते हुए फर्राटे से अपनी फेरारी मे निकल जाते हैं। जब ये सरकार को कोसते हैं तो उनका साहस देखकर किसी भी नए लेखक का अचंभित होना और पथभ्रमित हो जाना संभव है, किंतु निकट से विश्लेषण पर हम पाते हैं कि ये सरकार का विरोध करते हैं, सत्ता का नहीं। वर्तमान में सत्ता और सरकार का अर्थ भिन्न है। बहुधा तीक्ष्ण से तीक्ष्ण लेखन संपादकों की सजग दृष्टि के पार इसी विश्वास के कारण हो जाता है कि इसे पडता कौन है? इस व्यंग्य वीरता के पीछे भारतीय समाज का कान्वेंटीकरण है। हिंदी व्यंग्यकार अपनी साहित्यिक नगण्यता को लेकर आश्वस्त होता है अत- 'अपन किसी के बाप से नहीं डरते' का भाव लिखकर लेखनी उठाता हइस सारी गोल–मोल कथा का अभिप्राय यह है कि अंग्रेजी लेखक, जो अक्सर पत्रकार भी होता है, जो मंत्रिमंडल नियुक्तियों का अधिकार खोकर पुन- सत्ता और सरकार के एकीकरण को प्रयासरत रहता है, भले ही छद्म शौर्य पर तालियां जमा कर ले, महिमामंडित हो ले, साहस का फुल कोटा और अधिकार केवल और केवल हिंदी व्यंग्य लेखन को ही प्राप्त है। अंग्रेजी में एक शब्द है 'ब्रिंकमैनशिप' जिसका हिंदी अनुवाद– कुल्हाडी पर पैर मारने–की प्रवृत्ति माना जा सकता है। जब हम 70 के दशक में आपातकाल के आसपास शरद जोशी जैसे लेखकों को इंदिरा जी पर, भजनलाल जी पर लिखते देखते हैं तो पाते हैं कि यह प्रवृत्ति हिंदी व्यंग्यकारों में प्रचुर मात्रा में भरी है।

मुझे लगता है मेरा भी ऐसा स्वभाव है। इससे पहले आप मेरे इस प्रकार गाल बजाने से उत्साहित हो उठें, मैं अपने संदर्भ में इस प्रवृत्ति की तह में जाता हूं। वैसे तह तक जाने से मैं और आप बहुत ज्ञानी नहीं हो जाएंगे, किंतु फिर भी मैं जाऊंगा और मेरा निवेदन है कि आप भी आएं, क्योंकि मुझे तो अपनी बात हर हाल में कहनी ही है और चूंकि आप इन पंक्तियों को पड रहे हैं इसलिए मुझे यह भी पता है कि आपके पास समय है। सो तह तक जाने से मुझे लगता है कि हिंदी व्यंग्यकार के तौर पर अपने साहस के पीछे मेरा अपठनीय होना है और उपेक्षित होना है। बहुधा तीक्ष्ण से पार इसी विश्वास के कारण हो जाता है कि इसे पडता कौन है? इस व्यंग्य वीरता के पीछे भारतीय समाज का कान्वेंटीकरण है। हिंदी व्यंग्यकार अपनी साहित्यिक नगण्यता को लेकर आश्वस्त होता है अत- 'अपन किसी के बाप से नहीं डरते' का भाव लिखकर लेखनी उठाता है और वाम–दक्षिण का भेद त्यागकर उत्पात मचाता है। वह यह नहीं बताता कि इस वीरता के पीछे अपन को किसी का बाप भी नहीं पडता–वाला विश्वास भी है। विरले ही ऐसा कोई अवसर उत्पन्न होता है जब आपका लिखा हुआ कुछ पड लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि थोडा नरम कर दें, बदल दें। ऐसे समय हिंदी व्यंग्यकार उस मध्यवर्गीय बालक की भांति चमत्कृत सा हो जाता है जिसके अभिभावक उसे चलना–बोलना तो बडी शिद्दत से सिखाते हैं और फिर मौके की नजाकत के मुताबिक चुपचाप बैठ जाने को कह देते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत कम ही होता है। मेरे प्रकाशकों का भी मानना है कि इसके हाशिये पर हीरो बनने से किसी का कुछ बिगडना नही है। मेरा मानना है कि जैसा बौद्धिक कान्वेंटीकरण प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित भारतीय समाज में आज है, हिंदी व्यंग्यकार सुरक्षित भाव से व्यंग्य लिखे जा सकता है। साहित्यिक पुरस्कारों के अभाव में आप उन्हें लौटाकर समाज की दिशा और दशा तो बदल नहीं सकते हैं, सो बेखटके लिखें, आग उगलें और साहित्य के न सही रद्दी–कबाडी वालों के प्रिय लेखक बनने का प्रयास करें। यही मैं कर रहा हूं। मैं निरंतर लिखते रहकर रद्दीवालों के माध्यम से गृहिणियों को स्टील की कटोरियां दिलाने को कटिबद्ध हूं। मुझे विश्वास सा हो चला है कि कबाडी समाज रद्दी के निर्माण में बहुमूल्य योगदान के लिए एक न एक दिन मुझे महान साहित्यकार मानेगा। मेरी अपठित लेखक होने की छद्म वीरता एक दिन मुझे साहसी और जुझारू लेखक का सम्मान अवश्य देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे पदक और कप न मिलें, जिन्हें मैं जरूरत के वक्त लौटा सकूं, परंतु मैं अपने पाठकों को प्लेट और कटोरियां अवश्य दिलाऊंगा, ऐसा मेरा प्रयास है।

राज्यसभा में अरुण जेटली ने जवाब दिया

इतिहास बताएगा कश्मीर पर श्यामा प्रसाद सही थे या नेहरू

कश्मीर की समस्या कांग्रेस की लगातार गलत नीतियों का नतीजा हैं, जिनसें कांग्रेस को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, राज्यसभा में गुरुवार को जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर बहस के दौरान कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले साढ़े चार साल में कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ी है। आजाद ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा भंग करने को लेकर भी केंद्र सरकार की भूमिका को कठघरे में खड़ा किया। सरकार की ओर से पलटवार करते हुए अरुण जेटली ने आजाद को जवाब दिया कि कश्मीर की समस्या कांग्रेस की लगातार गलत नीतियों का नतीजा हैं, जिनसें कांग्रेस को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद ने कहा, कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है। जब तक इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक वो सरकारें गलती करेंगी, जो इतिहास से जुड़ी नहीं है। जो भी सरकारें बीच में आई, जिन्हें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी। १९४६ से कश्मीर में टू-नेशन थिअरी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राज्य में तोड़फोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। राज्यसभा में आजाद ने कहा कि इन चार साल में सबसे ज्यादा सघर्ष विराम तोड़ा गया और उससे सीधे स्थानीय नागरिकों को नुकसान होता है। आतंकवाद इन ४ साल में अपने चरम पर पहुंच गया है। सीजफायर में सबसे ज्यादा शहरी इन चार साल में मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि आपने खूब बाजे-गाजे के साथ कश्मीर में सरकार बनाई थी, लेकिन अब आप सभी मोर्चे पर विफल हो गए तो समर्थन वापस ले लिया। आजाद ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टिया समर्थन वाप लेती है लेकिन यहां तो केंद्र सरकार ने ही समर्थन वापस ले लिया। आजाद ने कहा कि आप वहां तोड़-फोड़ की कोशिश कर रहे थे, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जबकि इन्हीं दलों की सरकारों में वहां सबसे ज्यादा काम किया था। उन्होंने कहा कि हमें यह मंजूर नहीं है, वहां चुनाव कराने चाहिए थे। जेटली ने इसके जवाब में कहा, कश्मीर में जिस अलग अस्तित्व की कल्पना की गई थी, ७० बरसों में वह अलगाववाद की तरह बढ़ी। जो वादे कांग्रेस ने कर दिए, उसकी कीमत देश को कई बरसों तक अदा करनी पड़ी। आप सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में चलने के इतिहास को भू गए। १९५७, १८६२, १९६७ में जम्मू-कश्मीर में चुनाव कैसे होता था, उस पर काफी कुछ लिखा गया है।

अक्टूबर में जब सीमापर से हमला हुआ, तो प्रजा परिषद को लोगों ने अपना योगदान दिया। हम नेताओं का योगदान नहीं भूलेंगे, लेकिन आपको लोगों का योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी राजनीति के बाद आपक कहते हैं कि कश्मीर में पिछले साढ़े चार साल में अलगाववाद की भावना बढ़ी।

दुनिया के लिए समस्या बनता बेलगाम चीन, भारत को भी चौकसडरहने की जरूरत

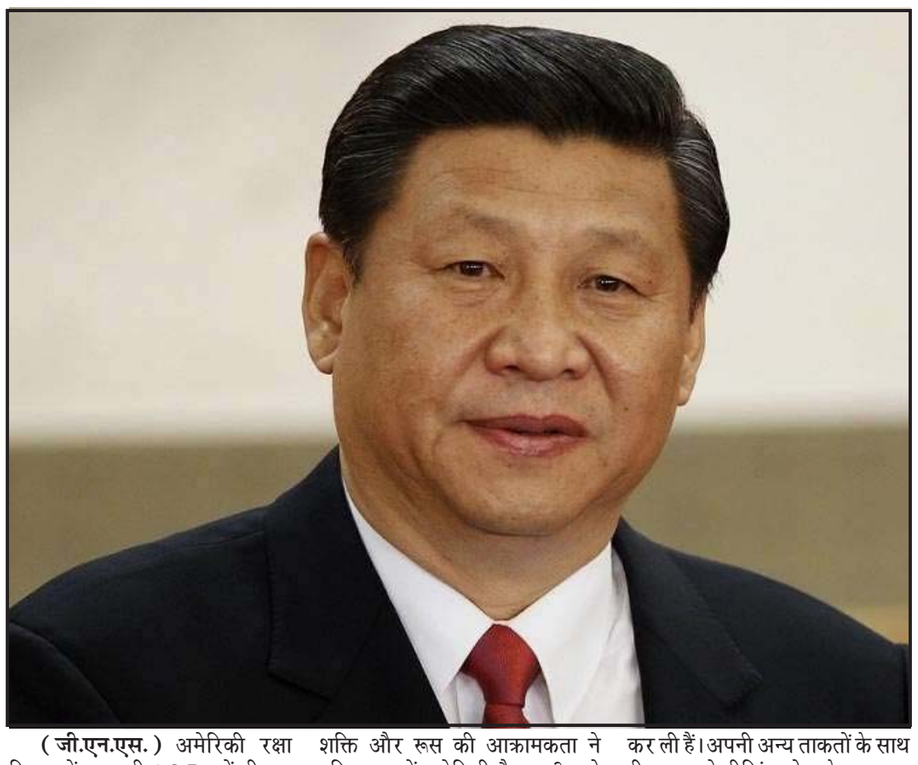

(जी.एन.एस.) अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की 125 पन्नों की एक हालिया रिपोर्ट में चीन की बडती सामरिक शक्ति पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके साथ ही बीजिंग दुनिया में आर्थिक साम्राज्यवाद की मुहिम भी चला रहा है। इसके लिए वह गरीब और विकासशील देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन कब्जाने की जुगत में है। उन देशों के बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उनके संसाधनों पर भी चीन की नीयत खराब है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका और एशिया तक दुनिया के हर कोने में चीन अपने पैर पसार रहा है। दुनिया भर के बाजार उसके सस्ते उत्पादों से पट रहे हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद करने पर तुले हैं। चीन के उभार के चलते बीते कुछ वर्षों में अमेरिका को हिंद–प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बडाने पर मजबूर होना पडा है। गत वर्ष जारी अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में रूस और चीन के साथ कडी प्रतिस्पर्धा की अहमियत पर जोर दिया गया था। इसमें दावा किया गया कि चीन की बडती सैन्य शक्ति और रूस की आक्रामकता ने दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य ब?त को कमजोर किया है। सैन्य मोर्चे पर चीन के भारी खर्च से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी बडी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। आधिकारिक रूप से बीजिंग रक्षा पर 157 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका का रक्षा बजट अभी भी 602 अरब डॉलर है। वहीं भारत ने भी 2017 में रक्षा पर 52 अरब डॉलर खर्च किए। इस खर्च का दूसरा पहलू भी है। अगर विनिमय दरों की तुलना से इतर वास्तविक सैन्य खर्च की बात करें तो यह काफी ज्यादा होगा। यहां तक कि क्रय शक्ति समानता और अन्य पैमानों को देखते हुए भी यह अधिक है। अमेरिका को चीन की सैन्य चुनौती अभी तक केवल पश्चिमी प्रशांत महासागर तक ही सीमित थी, लेकिन बीजिंग अब ऐसी क्षमताएं हासिल करने में जुटा है कि उसकी सैन्य शक्ति के दायरे का क्षेत्रीय पडोसियों से परे तक विस्तार हो। बीजिंग ने पांचवीं पीडी का उन्नत लडाकू विमान, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल और डीजल–इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की क्षमताएं हासिल कर ली हैं। अपनी अन्य ताकतों के साथ ही इन सबसे बीजिंग को न केवल पूरब और दक्षिण पूर्व एशियाई पडोसियों पर बडत हासिल हो जाती है, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हस्तक्षेप की राह रोकने में भी वह सक्षम हो गया है। रक्षा के मोर्चे पर उसकी तमाम कवायदें अब रंग ला रही हैं। ऐसे में अगर ताइवान या अमेरिका के दूसरे सहयोगियों का चीन के साथ संघर्ष छिडता है तो उनकी रक्षा के लिए अमेरिका के समक्ष चुनौती और कडी होगी। चीन ने बाइडू–3 सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही अपने अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम को बहुत दुरुस्त बना लिया है। इससे वह दुश्मन के ठिकानों पर बहुत बारीकी से निशाना लगा सकता है। चीनी सेना अब युद्ध के मैदान में वर्चस्व बना सकती है। पांचवीं पीडी के लडाकू विमान से लेकर लंबी रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के मिश्रण से चीन ने सैन्य मोर्चे पर ऐसी तरक्की की है जिसने दुनिया के सामने एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

ऐक्टर की नेट वर्थ १३०० करोड़ रुपये है

साउथ के सुपरस्टार राम चरण ने खरीदा ३८ करोड़ का घर

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, साउथ के सुपरस्टार राम चरण टॉलिवुड के सबसे अमीर ऐक्टर्स में से एक हैं। फिल्मों के अलावा वह ब्रैंड एंडोर्समेंट्स और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमाते हैं। अब खबर आई है कि राम चरण ने हैदराबाद में जुबली हिल्स की प्राइम लोकेशन में एक नया भव्य घर खरीदा है। बताया जा रहा है कि इस घर की कीमत करीब ३८ करोड़ रुपये है। सूत्रों की मानें तो यह घर दक्षिण भारत के किसी भी सिलेब्रिटी के सबसे महंगे घरों में से एक है। ऐक्टर की नेट वर्थ १३०० करोड़ रुपये है। बता दें, राम चरण का अपना प्रॉडक्शन हाउस भी है जिसका नाम कोनिडेला प्रॉडक्शन कंपनी है। उनके प्रॉडक्शन की अगली फिल्म में उनके पिता चिरंजीवी लीड रोल में नजर आएंगे। यह फिल्म तेलुगू, तमिल और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। इस फिल्म का बजट लगभग १५० करोड़ है जिसमें जगपति बाबू, नयनतारा और विजय सेतुपति जैसे ऐक्टर्स भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। वर्कफ्रंट की बात करें तो राम चरण अब एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में जूनियर एनटीआर के साथ नजर आएंगे। इस प्रॉजेक्ट से लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं क्योंकि राजामौली बाहुबली' और 'मगधीरा' जैसी फिल्में बना चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह फिल्?म ३०० करोड़ के बजट से तैयार होगी। मेकर्स इस फिल्म को २०२० संक्रांति के मौके पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं।

फिल्मों के अलावा वह ब्रैंड एंडोर्समेंट्स और पर्सनल इन्वेस्टमेंट से सुपरस्टार राम चरण पैसा कमाते हैं

वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका

राज्यसभा चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई का सामना करे अहमद पटेल

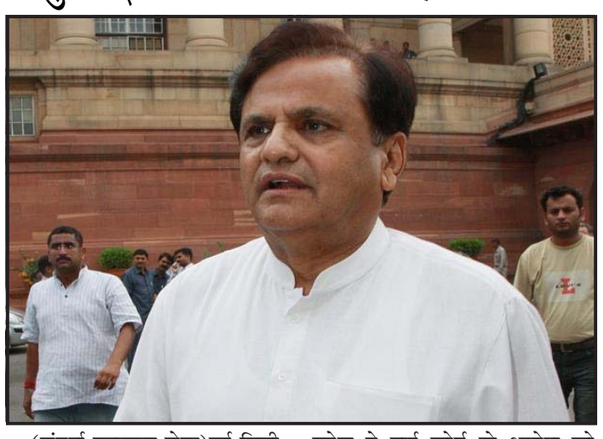

(संपूर्ण समाचार सेवा)नई दिल्ली, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटेल से राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई का सामना करने को कहा है। गुरुवार को कोर्ट ने पटेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि २०१७ में राज्यसभा के लिए उनके निर्वाचन को चुनौती देनेवाली उम्मीदवार बलवंतसिंह राजपूत की याचिका के संबंध में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में ट्रायल का सामना करना होगा। सर्वोच्च अदालत ने २६ अक्टूबर २०१८ को गुजरात हाई कोर्ट के आदेश में दखल से साफ इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस किशन कौल की पीठ ने अहमद पटेल की याचिका खारिज करते हुए कहा, सुनवाई होने दीजिए। पटेल ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राजपूत की चुनावी याचिका पर विचार करने पर सवाल उठानेवाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपनी चुनावी याचिका में राजपूत ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दो विद्रोही विधायकों के वोटों को अवैध करार दिया गया था। बीजेपी नेता ने दलील दी थी कि क्या उनके वोटों को गिना गया था, उन्होंने पटेल को हरा दिया होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है।कोर्ट ने गुरुवार को कहा, चूंकि सभी पार्टियां मौजूद है इसलिए औपचारिक तौर पर नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। अगली सुनवाई फरवरी में होगी। इस बीच हाई कोर्ट चुनावा याचिका पर सुनवाई को आगे बढ़ा सकता है।

खरीदी के साथ साथ

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

- १५ नवम्बर से ३ जनवरी तक खरीदी
- गुजरातभर के १,१९,२७९ किसानो के पास से समर्थन मूल्य पर मुंगफली की खरीदी
- गुजरात सरकार ने २३,७९,८३३ क्विन्टल मुंगफली की खरीदी की
- ४ जनवरी से अधिक से अधिक किसानो के पास से मुंगफली की खरीदी होगी
- २५०० किलोग्राम की मर्यादा में मुंगफली लाने के लिए किसानो को जानकारी दी गई थी
- १२२ एपीएमसी सेन्टर पर से १ नवम्बर से मुंगफली की खरीदी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु हुई थी
- किसानो को पोषणयुक्त भाव देने के हेतु से बड़े पैमाने पर किसानो के पास से खरीदी

सारा अली खान को सिंबा में काफी पसंद किया

डायरेक्टर कन्नन अय्यर की अगली फिल्म में होंगी सारा

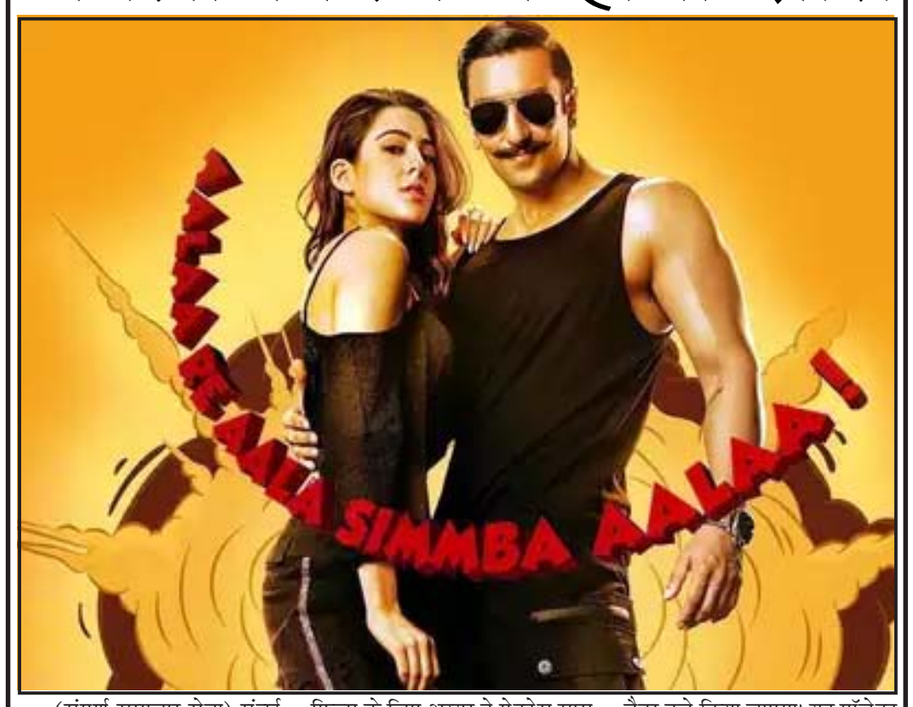

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, २०१३ में रिलीज हुई डायरेक्टर कन्नन अय्यर की फिल्म 'एक थी डायन' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था लेकिन इसके डायरेक्टर अब नई कहानी के साथ कमबैक करने को तैयार हैं। खबर है कि अपनी नई फिल्म के लिए अय्यर ने ऐक्ट्रेस सारा अली खान को फाइनल कर लिया है। बता दें, सारा की पिछली फिल्म 'सिंबा' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था और करीब २०० करोड़ की कमाई की थी।सूत्रों के मुताबिक, कन्नन अय्यर की फिल्म एक बायॉपिक होगी और इसका निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रॉडक्शन्स के बैनर तले किया जाएगा। यह प्रॉजेक्ट अगस्त २०१९ में फ्लोर पर जा सकता है। हालांकि, इस पर फाइनल डीटेल्स आना बाकी है। इससे पहले सारा अली खान को सिंबा के अलावा फिल्म केदारनाथ में भी काफी पसंद किया गया था। उनकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था।

२०१३ में रिलीज हुई डायरेक्टर अय्यर की फिल्म 'एक थी डायन' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर सकी थी

आईसीसी वनडे रैंकिंग में धोनी की छलांग

धोनी बल्लेबाजों की रैंकिंग में १७वें स्थान पर आ गये

(संपूर्ण समाचार सेवा) दुबई, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लगातार ३ अर्धशतक मारने वाले भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की सोमवार को जारी ताजा रैंकिंग में ३ स्थान ऊपर आ गए हैं। यह दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज अब बल्लेबाजों की रैंकिंग में १७वें स्थान पर आ गया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई तीन वनडे मैचों की सीरीज में क्रमशः ५१, नाबाद ५५ और नाबाद ८७ रनों की पारी खेली थी। उनके इस प्रदर्शन ने भारत को पहली बार ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने में मदद की। भारतीय मध्यक्रम में एक और मजबूत कड़ी बनकर उभरे केदार जाधव को भी ८ स्थान का फायदा हुआ है। वह अब ३५वें स्थान पर आ गए हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अपना पहला स्थान कायम रखा है। आखिरी दो मैचों में कोहली को आराम दिए जाने के बाद कप्तान की जिम्मेदारी संभालने वाले रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। रोहित के सालमी जोड़ीदार शिखर धवन ७४४ अंकों के साथ १०वें स्थान पर हैं। आईसीसी वनडे गेंदबाजी में भी भारत ने अपना वर्चस्व दिखाया है। जसप्रीत बुमराह पहले स्थान पर कायम हैं, जबकि चाइनामैन कुलदीप यादव और लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल क्रमशः चौथे और ५वें स्थान पर हैं। टीम रैंकिंग में भारत १२२ अंकों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है, जबकि भारत के हाथों १-४ से शिकस्त झेलने वाली किवी टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है।

धोनी ने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई वनडे मैचों की सीरीज में क्रमशः ५१, नाबाद ५५, ८७ रनों की पारी खेली

दहीया गैंग के फरार चल रहे आरोपियों की जांच बाकी

पेपर लीक घोटाले में गिरफ्तार किए ३ के दस दिन की रिमांड

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात सहित देशभर में खलबली मचाने वाले लोकरक्षक भर्ती दल पेपर लीक घोटाले में गिरफ्तार किए गए दहीया गैंग के तीन आरोपी हरियाणा के सोनीपत के विनय रमेशकुमार अरोरा, कर्नाटक के बीडर के निवासी महादेव दत्तात्रेय अस्तुर और विनोद बंसीलाल राठोड को कोर्ट ने दस दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने गुरुवार को यह तीनों आरोपियों को पुलिस बंदोबस्त के बीच गांधीनगर कोर्ट में पेश करके १४ दिन के रिमांड की मांग की गई थी। पुलिस की तरफ से आरोपियों की रिमांड अर्जी में बताया गया है कि, आरोपी गुजरात सहित अन्य राज्यों में पेपर लीक घोटाले में शामिल है और उनके विरूद्ध इस मामले में कई अपराध दर्ज किए गए हैं। प्रस्तुत केस में आरोपियों ने कर्नाटक के मनीपाल प्रिन्टिंग प्रेस से पेपर लीक कराया इसमें उनको मदद करने वाले और फरार चल रहे तीन आरोपियों की जानकारी उनके पास लेना है।उल्लेखनीय है कि, अहमदाबाद क्राइमब्रांच, एटीएस और गांधीनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में पेपर लीक घोटाले में मुख्य सूत्रधार दहीया गैंग के तीन आरोपी हरियाणा के सोनीपत के विनय रमेशकुमार अरोरा, कर्नाटक के बीडर के निवासी महादेव दत्तात्रेय अस्तुर और विनोद बंसीलाल राठोड को पुलिस ने गत दिन गिरफ्तार करके पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया था। रहे सुराग की जांच करना बाकी है, इसी वजह से कोर्ट को उनका १४ दिन का रिमांड मंजूर करना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी ध्यान में लेकर तीन आरोपियों के दस दिन के रिमांड मंजूर किए गए थे। पुलिस ने गुरुवार को यह तीनों आरोपियों को पुलिस बंदोबस्त के बीच गांधीनगर कोर्ट में पेश करके १४ दिन के रिमांड की मांग की गई थी। पुलिस की तरफ से आरोपियों की रिमांड अर्जी में बताया गया है कि, आरोपी गुजरात सहित अन्य राज्यों में पेपर लीक घोटाले में शामिल है और उनके विरूद्ध इस मामले में कई अपराध दर्ज किए गए हैं। प्रस्तुत केस में आरोपियों ने कर्नाटक के मनीपाल प्रिन्टिंग प्रेस से पेपर लीक कराया इसमें उनको मदद करने वाले और फरार चल रहे तीन आरोपियों की जानकारी उनके पास लेना है। यह पूरे मामले में अभी अन्य आरोपी फरार चल रहे है, इसी वजह से उनके मामले में भी जानकारी लेना है। आरोपियों को साथ में रखकर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक सहित के विभिन्न राज्यों में और स्थलों पर जांच करना है और पूरे घोटाले में कम हो

पुलिस ने १४ दिन के रिमांड की मांग की थी : पेपर लीक घोटाले में अभी और सुराग जुटाने में लगी हुई है

आनंदनगर की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी

प्लेटिनम इन होटल में लिफ्ट में फंसने से किशोर की मौत

आनंदनगर में प्लेटिनम इन होटल में बर्तन साफ का काम करता था : आनंदनगर पुलिस ने जांच शुरू की

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, आनंदनगर में स्थित प्लेटिनम इन होटल की लिफ्ट में गुरुवार को अचानक किसी वजह से फंस जाने से मेहुल मारवाडी नाम के १२ वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी। किशोर की मौत को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। दूसरी तरफ, होटल में स्टाफ कर्मचारियों और मैनेजमेन्ट में भगदड़ मच गई थी । घटना की जानकारी मिलने से पुलिस और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पूरे मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, शहर के आनंदनगर में स्थित प्लेटिनम इन होटल में मेहुल मारवाडी नाम का १२ वर्षीय किशोर बर्तन साफ करने का काम करता था। पिछले पांच महीने से इस होटल में काम करते होने का सामने आया है। गुरुवार को होटल की लिफ्ट में जाते समय वह अचानक फंस जाने से इसकी मौत हो गई थी। यदि किशोर लिफ्ट में किस तरीके से और किस परिस्थिति में फंस गया यह रहस्यमय बन गया है। पुलिस ने इस दिशा में जांच शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि, प्लेटिनम इन होटल के मैनेजमेन्ट द्वारा मृतक के परिवार को मेहुल की मौत होने की एक घंटे के बाद जानकारी दी गई थी। जिसकी वजह से परिवार ने भी किशोर का शव स्वीकार करने से मना कर दिया। दूसरी तरफ घटना की जानकारी मिलने पर आनंदनगर पुलिस का स्टाफ भी तुरंत होटल पर पहुंच गया और होटल के स्टाफ कर्मचारियों की पूछताछ करके पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच के तहत एफएसएल की टीम को जानकारी देने पर वह भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और जरूरी सेम्पल लिया गया। उल्लेखनीय है कि, १४ वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना अपराध है। किशोर की मौत को लेकर पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। दूसरी तरफ, होटल में स्टाफ कर्मचारियों और मैनेजमेन्ट में भगदड़ मच गई थी । घटना की जानकारी मिलने से पुलिस और एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और पूरे मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, शहर के आनंदनगर में स्थित प्लेटिनम इन होटल में मेहुल मारवाडी नाम का १२ वर्षीय किशोर बर्तन साफ करने का काम करता था। पिछले पांच महीने से इस होटल में काम करते होने का सामने आया है। गुरुवार को होटल की लिफ्ट में जाते समय वह अचानक फंस जाने से इसकी मौत हो गई थी।बाल मजदूरी कराने वाले को अब ६ महीने से लेकर २ वर्ष तक की जेल की सजा या २० हजार से ५० हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। कानून के अनुसार किसी भी बच्चे को नौकरी पर नहीं रखा जा सकता है।

११८९ करोड़ रुपये की मुंगफली की खरीदी

११९२७९ किसानो के पास से मुंगफली की खरीदी हुई

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, गुजरात सरकार ने किसानो को बड़ी राहत देने के इरादे से उनके पास से समर्थन मुल्य पर मुंगफली खरीदने का निर्णय किया है। जिसके तहत १५ नवम्बर लेकर ३ जनवरी तक राज्य में कुल १,१९,२७९ किसानो के पास से गुजरात सरकार ने अब तक समर्थन मुल्य पर ११८९ करोड़ की कीमत की २७,७९,८३३ क्वीन्टल मुंगफली खरीदी है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि सरकार की ओर से खरीफसीजन २०१८-१९ के लिए न्युनत्तम समर्थन मुल्य से मुंगफली की खरीदी के लिए १५ नवम्बर से खरीदी शुरु की गई थी। मुंगफली खरीदी के केन्द्र के रुप में घोषित किए गए राज्य के कुल १२२ एपीएमसी सेन्टर पर संबंधित जिल्ला क्लेक्टरो की ओर से १ नवम्बर २०१८ से समर्थन मुल्य पर किसानो के पास से मुंगफली खरीदने के लिए किसानो की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरु की गई थी। यह रजिस्ट्रेशन के अनुसार सरकार के नियम अनुसार हर रोज २५०० किलोग्राम की मर्यादा की लाने के लिए किसानो को एपीएमसी की ओर जानकारी दी गई थी। जिसके परिणाम स्वरुप किसान अपनी मुंगफली को बेचने के लिए पहुंचे थे। प्रक्रिया के तहत ३ जनवरी तक राज्य सरकार ने निर्धारित किए गए लघुत्तम समर्थन मुल्य प्रति क्वीन्टल रुपए ५ हजार के अनुसार राज्यभर के १,१९,२७९ किसानो के पास से कुल ११८९ करोड़ की कुल २३,७९,८३३ क्वीन्टल मुंगफली की खरीदी की है। जानकारी में बताया गया है कि खरीद केन्द्रो पर जरुरी संख्या में वजन कांटे रखे गए थे।

शिवराज सिंह चौहान ने दी अपनी प्रतिक्रिया

जहां भी जाता हूं, लोग मेरा हीरो की तरह स्वागत करते

शिवराज ने कहा भले हालिया चुनाव में बीजेपी हार गई हो लेकिन लोग अभी उनका हीरो की तरह स्वागत करते

(संपूर्ण समाचार सेवा) भोपाल,

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि भले ही बीजेपी सरकार नहीं बना पाई हो लेकिन जनता अब भी उन्हें हीरो मानती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के हेड ऑफिस में एक सोशल मीडिया वर्कशॉप को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भले ही हालिया चुनाव में बीजेपी हार गई हो लेकिन लोग अभी भी उनका हीरो की तरह स्वागत करते है। वर्कशॉप में शिवराज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, हम भले ही विधानसभा चुनाव में हार गए हों, लेकिन लोगों का मेरे लिए प्यार अभी भी है। मैं जहां कहीं जाता हूं, मेरा एक हिरो की तरह स्वागत होता है। लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क समझ चुके हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए वे बीजेपी के सत्ता में लौटने की उम्मीद रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जब मैंने जनता से पूछा कि हमसे क्या भूल हुई, तो लोग बोले-भूल हमसे हो गई मामा, अब हम उसे सुधार लेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव की लड़ाई सोशल मीडिया पर कैसे लड़ी जाए, इस पर भी टिप्स दिए। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव एक धर्मयुद्ध है। यह लड़ाई देशभक्तों और विभाजनकारी ताकतों के बीच है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। न ही किसी शक्स का चुनाव होना है। यह भारत को बचाने के लिए चुनाव है। बीजेपी नेता ने सोशल मीडिया का महत्व बताते हुए कहा, जनता की मदद से कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। चाहे या महागठबंधन के खिलाफ हो या किसी सिंगल पार्टी के।

महाराष्ट्र : फडणवीस सरकार का फैसला

१०% कैटिगरी आरक्षण पर लगाई मुहर : रिपोर्ट में दावा

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग के गरीबों को १० प्रतिशत आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। केंद्र सरकार की तरफ से १० प्रतिशत जनरल कैटिगरी आरक्षण पर पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी है। हाल ही में मोदी सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जनरल कोटा को मंजूरी दी थी। संसद से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत करते हुए मुहर लगा दी थी। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें सामान्य वर्ग को १० फीसदी आरक्षण के प्रावधान का रास्ता साफ करते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसके तहत अब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटिगरी के दावेदारों को आरक्षण मिलेगा। बता दें कि इस आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगो को मुहैया कराया जाएगा, जिनकी सालाना आय ८ लाख रुपये से कम हो। केंद्र सरकार की नौकरियों में १ फरवरी से जनरल कैटिगरी के गरीबों को आरक्षण लागू किया गया है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में जनरल कोटा के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद १५ और १६ में संशोधन के जरिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। यह सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर किसी तबके के नागरिक की तरक्की के लिए विशेष प्रावधान करने की इजाजत देता है। २०१९ के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के इस कदम को मास्टरस्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है।

२० लाख की फिरौती के साथ चार गिरफ्तार

अपहृत व्यापारी को पुलिस ने राजस्थान से मुक्त कराया

छह दिन पहले व्यापारी का अपहरण : क्राइमब्रांच ने उदयपुर एसटीएफ को साथ में रखकर ऑपरेशन किया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद

अहमदाबाद के व्यापारी और नाना चिलोडा के पास कलर का धंधा करते व्यापारी हनुमंतसिंह राजपूत का गत २८ तारीख को शाम के समय में अपहरण हुआ। इसके बाद हनुमंतसिंह को छोड़ने के लिए अपहरणकर्ताओं द्वारा २५ लाख रुपये की मांग की गई थी। यह अपहरण की घटना को लेकर आखिर में अहमदाबाद क्राइमब्रांच ने गत दिन रात को उदयपुर स्पेशियल टास्क फोर्स की मदद से ऑपरेशन शुरू करके अपहृत हनुमंतसिंह को छुड़ा लिया गया और इसके साथ ही चार अपहरणकर्ता को २० लाख रुपये की फिरौती के साथ गिरफ्तार किया गया। छह दिन बाद मुक्त हुए व्यापारी और इसके परिजनों ने काफी राहत महसूस की। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद के सरदारनगर में रहते और नाना चिलोडा के पास कलर का धंधा हनुमंत सिंह राजपूत २८ तारीख की रात को ८ बजे अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहे थे तब रास्ते से अज्ञात लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। वह देर शाम को घर नहीं पहुंचने से परिजनों ने जांच शुरू कर दी लेकिन उनका फोन भी स्वीच ऑफ हो गया। इस दौरान हनुमंतसिंह के भागीदार का एक फोन आया और उनको जानकारी दी गई कि, हनुमंतसिंह का अपहरण हुआ है और उनको छोड़ने के लिए २५ लाख रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार की फिरौती मांगने पर परिजन डर गये थे, इस मामले में पुलिस को जानकारी मिलने पर उन्होंने यह अपहरण मामले को गुप्त रखा गया था पुलिस को डर था कि अपहरण कर्ता डर की वजह से हनुमंतसिंह को नुकसान पहुंचा सकते है। दूसरी तरफ पूरे मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर अहमदाबाद क्राइमब्रांच सक्रिय हो गई थी और उन्होंने अपहरणकर्ता को ढूढ़ने के लिए कवायद शुरू कर दी। दूसरी तरफ क्राइमब्रांच ने हनुमंतसिंह के भागीदार को अपहरणकर्ता के साथ संपर्क चालू रखने के लिए कहा गया। अपहरणकर्ता ने आखिर में २० लाख रुपये के साथ आने की सूचना दी थी। उदयपुर एक गांव के पास पैसे देने का तय किया गया और हनुमंतसिंह के भागीदार को बुलाया गया। पुलिस अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करे तो हनुमंतसिंह की हत्या हो जाएगी इसी वजह से उनके भागीदार को सूचना दी गई आप पैसे देकर हनुमंतसिंह को लेकर निकल जाओ। शनिवार रात के ८ बजे पैसे चुकाने के बाद हनुमंतसिंह वहां से निकल गये इसके बाद क्राइमब्रांच और एसटीएफ ने ऑपरेशन शुरू करके चार अपहरणकर्ता और उनके पास रहे २० लाख रुपये भी जब्त कर लिए गए थे। व्यापारी की मुक्ति होने की वजह से परिजनों में खुशी की लहर फैल गई।

टीएमसी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं

बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड की गई, टीएमसी पर आरोप

(संपूर्ण समाचार सेवा) कोलकाता,

पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच संघर्ष और उग्र हो गया है। कल रात ममता बनर्जी के धरने पर बैठने के बाद से ही टीएमसी कार्यकर्ता प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि भवानीपुर मे बीजेपी के ऑफिस मे तोड़फोड़ की गई है। बंगाल बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक विडियो अपलोड किया है। इसमें बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद फर्नीचर इत्यादित के टूटे-फूटे होने का द्रश्य देखा जा सकता है। बीजेपी ने ट्विटर पर विडियो अपलोड करने के साथ ममता बनर्जी के समर्थकों को गुंडा करार दिया है। बंगाल बीजेपी ने बताया है कि साउथ कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी ऑफिस में ममता बनर्जी के गुंडों ने तोड़फोड़ की है। भवानीपुर ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि प्रदेश में लॉ ऐंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। टीएमसी शासन के अंतर्गत कोई भी सुरक्षित नहीं है।

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिक्रिया

एनडीए की वापसी पर साथ आने की कोशिश करेंगे नायडू

मुझे विश्वास है चुनाव खत्म होंगे, एनडीए सत्ता में वापसी करेगा, तब नायड साथ आने की कोशिश करेंगे : शाह

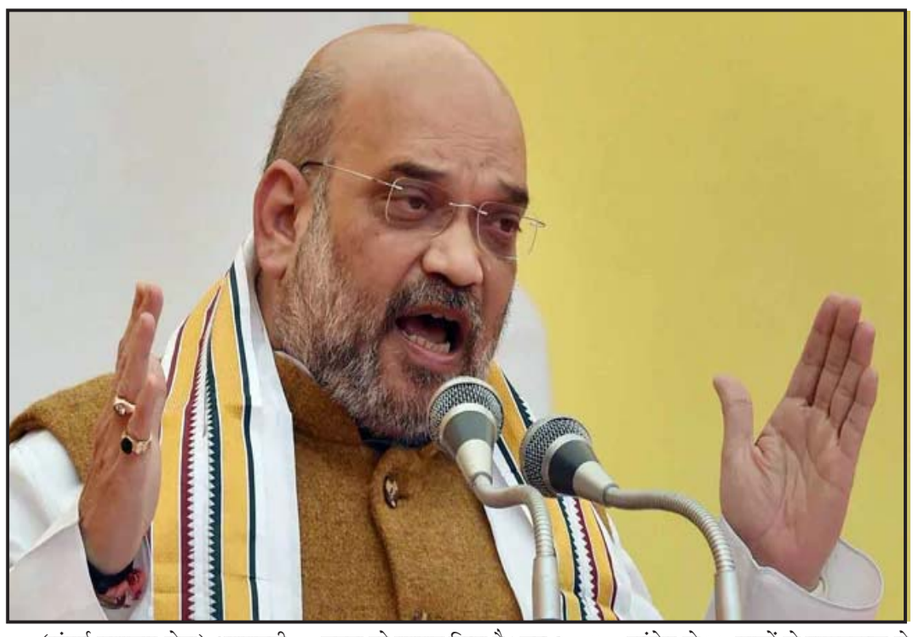

(संपूर्ण समाचार सेवा) अमरावती,

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को आंध्र प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया। अमित शाह ने मैसनिक टेंपल ग्राउंड में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने नायडू को यू-टर्न मुख्यमंत्री करार दिया। अमित शाह ने कहा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की जनता को गुमराह किया है। जब २००४ तक अटलजी की सरकार थी तो वह उनके साथ थे, २००४ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसके साथ हो लिए। वह एक बार फिर कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं जिसने आंध्र प्रदेश का अपमान किया। उन्होंने कहा, मुझे पुरा विश्वास है कि २०१९ में जब लोकसभा चुनाव खत्म होंगे और एनडीए सत्ता में वापसी करेगा, तब चंद्रबाबू फिर से एनडीए के साथ आने की पुरी कोशिश करेंगे। उन्होंने आगे कहा, एनडीए सरकार ने आंध्र प्रदेश के विकास के लिए जो किया वह कांग्रेस के ५५ सालों के शासनकाल से १० गुना ज्यादा है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने राज्य में २० अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थान खोलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कई प्रॉजेक्ट्स को शुरू किया है जिनमें एम्स का निर्माण, आईआईटी, आईआईएम का निर्माण भी शामिल है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया, मैं उनसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने उस एनडी का साथ क्यों छोड़ा।

सुनंदा पुष्कर मौत केस में मुश्किलें कम नहीं हुई

२१वी को थरूर पर मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट करेगा

अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया : अब सेशंस में होगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस संसद शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में मुश्किलें कम नहीं हो रही है। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने केस को सेशंस कोर्ट में रेफर कर दिया है। अब थरूर से जुड़े मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में ही होगी। स्वामी ने कोर्ट से सुनवाई में सहयोग की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील भी खारिज कर दी। केस की सुनवाई के लिए २१ फरवरी की तारीख तय की गई है। बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर आरोपी है। २०१४ में सुनंदा की मौत दिल्ली के एक आलीशान होटल में हुई थी। शुरू में इसे आत्महत्या माना जा रहा था। इस मामले में शुरुआत से ही बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी हत्या का दावा कर रहे है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख २१ फरवरी को तय की है। बता दें कि शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी माना है। कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी मानते हुए आदेश जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ३००० पन्नो की विस्तृत चार्जशीट दायर की है। बता दें कि इस केस के सिलसिले में कई बार कांग्रेस नेता से दिल्ली पुलिस लंबी पुछताछ भी कर चुकी है। अब थरूर से जुड़े मामले की सुनवाई सेशंस कोर्ट में ही होगी। स्वामी ने कोर्ट से सुनवाई में सहयोग की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील भी खारिज कर दी। केस की सुनवाई के लिए २१ फरवरी की तारीख तय की गई है। बता दें कि सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में थरूर आरोपी है। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख २१ फरवरी को तय की है। बता दें कि शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी माना है।

तृणमूल कांग्रेस की शिकायत की

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सरकार पर पश्चिम बंगाल में उसके राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होने देने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की ताकि लोकसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से हो सके। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा कि भाजपा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात को प्रमुखता से पेश करने के लिए चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा कि तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। इस प्रतिनिधिमंडल में सीतारमण के अलावा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, एस एस अहलूवालिया और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय भूपेन्द्र यादव, अलनि बलूनी और मकुल रॉय थे ।

नैशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई होगी

एजेएल की याचिका पर २३ फरवरी को होगी सुनवाई

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली

नैशनल हराल्ड मामले में अगली सुनवाई २३ फरवरी को होगी। असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में चुनौती देते हुए २१ दिसंबर के फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इसे अलावा यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग को खाली किए जाने के आदेश पर रोक लगाना जरूरी है। इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए २३ फरवरी की तारीख तय की गई है। इससे पहले २१ दिसंबर को कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने नैशनल हेराल्ड के दिल्ली ऑफिस को खाली कि जाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एजेएल ने कोर्ट में नैशनल हेराल्ड हाउस की लीज रद करने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थीहेराल्ड का दफ्तर पिछले १० वर्षो से खाली पड़ा था। एजेएल ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में नैशनल हेराल्ड हाउस की लीज रद करने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। अदालत में सोमवार को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गाधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले में बीजेपी नेता व सुब्रमण्यम स्वामी से जिरह शुरु की। दोनों नेताओं ने अपने वकील के जरिए स्वामी से जिरह शुरु की जिन्होंने इस मामले में उनके खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत दायर कराई।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH